DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— Hindustan Times DATED— 23/06/2022

LG suspends 2 SDMs, official posted in CM office on corruption charges

Sweta Goswami
sweta.goswami@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant Governor (LG) Vinai Kumar Saxena on Wednesday ordered the suspension of three officials in the Delhi government over alleged corruption charges involving government land, senior officials in the LG office said on Wednesday.

Of the three officers, who will now face an internal inquiry by the revenue department, one was posted as a deputy secretary in chief minister's office (CMO) and the other two were sub-divisional magistrates (SDMs).

"Reiterating zero tolerance to corruption and probity in government functioning, the LG has ordered the suspension of Prakash Chand Thakur, deputy secretary in the CMO, Harshit Jain, SDM of Vasant Vihar and Devender Sharma, SDM of Vivek Vihar. Now, disciplinary proceedings will be initiated against these officers which involves an inquiry to be conducted by the revenue department," said a Raj Niwas official who asked not to be named.

All three officers belong to the Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service (DANICS) cadre.

The Delhi government did not comment on the matter, but a senior official in the CM Office said Thakur was one of the 5-6 deputy secretaries posted there.

A second senior official in the LG office said all the three cases pertain to corruption involving government land which was allegedly sold to private entities.

"Prima facie, procedural lapses were found in all three cases which indicated financial irregularities," the official said.

The move after two assistant engineers of the Delhi Development Authority (DDA) were suspended on June 17 after the LG visited flats constructed for economically weaker sections (EWS) at Kalkaji extension and found the work substandard and incomplete.

Though the Aam Aadmi Party (AAP) did not issue any formal statement on the matter, a senior party functionary said that the case involving Thakur took place before he was transferred to the CMO as deputy secretary.

Government records showed that Thakur's posting at the CMO was done along with the transfer of nine other officials on September 15, 2020.

He was then serving as an SDM at the headquarters of the revenue department in Civil Lines.

"Transfer and postings are done by the services department which comes under the direct control of the LG. We have no control on which officer comes and goes in various departments. It is all reviewed and approved by the LG. This case in which Thakur is being investigated is regarding some government land that was allegedly sold to some private entity in Narela zone," the senior AAP functionary said.

Meanwhile, the Delhi BJP alleged that the suspension of a CMO official has exposed the "hollowness" of honest governance claim by the ruling party.

"The CM claims zero tolerance on corruption, but today a black sheep has been found in his own office. This indicates that there is no monitoring against corruption in the CM office and the Delhi government secretariat," said Praveen Shankar Kapoor, spokesperson for Delhi unit of the Bharatiya Janata Party (BJP).

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME 6 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 23 जून, 2022 ---DATED---

वर्षा के पानी को सहेज कर भूजल स्तर बढ़ाने की तैयारी

- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विभिन्न एजेंसियों के उच्चाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
- 15 जुलाई तक 1548 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाकर तैयार कर लेगी दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली: दिल्ली में वर्षा जल को सहेजकर रखने का काम शुरू किया जा रहा है। इस साल वर्षा जल को एकत्र करने के लिए दिल्ली में 1500 से अधिक नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाए जा रहे हैं, जो 15 जुलाई से पहले बन जाएंगे। मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, डीडीए, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और नए बनाए जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स से संबंधित तैयारी का जायजा लिया।

योजना के तहत विभिन्न नोडल एजेंसियों के साथ मिलकर 1548 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाए जाएंगे। इसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 2475 हो जाएगी। वर्षा जल को व्यर्थ जाने से रोककर इन पिट्स को भरा जाएगा, जिसकी मदद से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर पाएंगे और बरसात में व्यर्थ बहने वाले लाखों लीटर पानी को एकत्र कर पाएंगे। सरकार का प्रयास है कि सभी नोडल एजेंसियां रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाने के काम को तेजी से पूरा करें, ताकि मानसून के दौरान इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

सरकार दिल्ली को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस बाबत

> वर्षा जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और दिल्ली जैसे शहर के लिए इसे सहेजकर रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर हैं। हम भूजल स्तर बढ़ाना चाहते हैं, ताकि पानी के मामले में दिल्ली आत्मनिर्भर बन सके।
>
> **मनीष सिसोदिया**
> उपमुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वैन से मुलाकात कर वहां के वर्षा जल संरक्षण माडल को समझा था। फ्रेडी स्वैन ने बताया था कि कैसे वर्षा जल को संरक्षित कर डेनमार्क ने खुद को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाया है। सरकार डेनमार्क के उन माडल को अपनाने का विचार कर रही है।

ऐसे काम करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट: रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की कार्यप्रणाली बहुत सामान्य है, जिसमें जमीन पर खोखला गड्ढे बनाए जाते हैं। मानसून के दौरान वर्षा जल को इन गड्ढों के माध्यम से एकत्र किया जाता है और यह पानी जमीन के अंदर जाता है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, JUNE 23, 2022

Govt to ready 1,500 rainwater harvesting pits before July 15

Times News Network

New Delhi: The Delhi government will ready 1,500 rainwater harvesting pits before July 15, deputy chief minister Manish Sisodia said on Wednesday.

"Rainwater is an important natural resource, especially for Delhi, because we are dependent on neighboring states for water. Collection of water through these pits will help us recharge groundwater levels and meet the capital's water requirements. We are creating 1,540 pits," said Sisodia.

According to the government, the work is going on a war footing. To review the progress, Sisodia held a meeting with senior officials of the public works department, Delhi Jal Board, Delhi Development Authority, irrigation and flood control department and the civic bodies.

Sisodia asked the officials to complete the work on priority to make the maximum use of the monsoon season. As per the weather department, the monsoon is likely to hit the city by the end of this month.

"The number of pits will increase to 2,475 and will help us store millions of gallons of water, which is often wasted. The project has a lot of potential to increase water supply and will help us become self reliant," reiterated Sisodia. The Delhi government often finds itself cornered due to water supply problems.

Recently, chief minister Arvind Kejriwal met a delegation of experts led by the ambassador of Denmark, Freddy Swain, to study his country's rainwater harvesting and groundwater recharge system. The experts presented a detailed analysis of Denmark's efforts and the Delhi government is reportedly planning to adopt a few of them to improve water supply in the capital.

Rainwater harvesting is a technique of collection and storage of rainwater into natural reservoirs or tanks, or that of infiltration of surface water into the subsurface level. The pits are actually soak pits, which are used to collect rainwater.

> **Times View**
>
> An overwhelmingly high percentage of rainwater received by the capital goes waste. One hopes that this campaign is carried out in all seriousness. Every drop of rain is like a liquid pearl for the city. As pointed out before, Delhi urgently needs a rainwater harvesting mission.

बिना नोटिस के डीडीए ने तोड़े घर, 17 परिवार बेघर : विशेष रवि

विशेष रवि • जागरण

जा.,नई दिल्ली: दिल्ली एससी-एसटी वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन व करोलबाग के विधायक विशेष रवि ने आरोप लगाया है कि डीडीए ने बिना नोटिस के घर तोड़ दिए हैं। महरौली क्षेत्र के वार्ड एक के 6/4 में डीडीए की इस कार्रवाई से एससी-एसटी समुदाय के 17 परिवार बेघर हो गए हैं।

विधायक के मुताबिक यह मामला 15 जून का है, जब डीडीए ने बिना किसी सूचना के आनन-फानन में नियमों की अनदेखी कर 40 साल पुरानी कालोनी के मकान तोड़े, जबकि निवासियों के पास बिजली का बिल व मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य वैध दस्तावेज थे।

उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र व राज्य सरकार के पुनर्वास नियमों का साफ उल्लंघन हुआ है, क्योंकि नियमानुसार सभी परिवार को पहले किसी अन्य जगह पर रहने के लिए घर दिए जाते। मामले में उन्होंने डीडीए, दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।

विशेष रवि ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कुछ होटल और शोरूम मालिकों की मिलीभगत से हुई है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रतिष्ठान के सामने इस तरह की बस्ती हो।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------------------

हिन्दुस्तान

कार्रवाई : मुख्यमंत्री कार्यालय के उप सचिव समेत तीन भ्रष्टाचार में निलंबित

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता। भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, इनमें मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक उप सचिव और दो एसडीएम शामिल हैं। मंगलवार को हौज खास में तैनात सब रजिस्ट्रार को भी निलंबित किया गया था।

कार्यभार संभालने के साथ ही उप राज्यपाल ने भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने और सरकारी कामकाज में ईमानदार कार्यप्रणाली को बनाए रखने का संदेश दिया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उप सचिव पीसी ठाकुर, वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन और विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उपसचिव पीसी ठाकुर पर कार्रवाई उनके नरेला में एसडीएम रहने के दौरान जमीन के हस्तांतरण में गड़बड़ी के आरोपों पर की गई।

हौज खास के सब रजिस्ट्रार पर भी कार्रवाई

हौजखास में तैनात सब रजिस्ट्रार डी सी साहू को भी निलंबित कर दिया गया है। मुख्य सचिव की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई। साहू को बगैर अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा गया है।

दो दिन पहले दो सहायक अभियंता सस्पेंड किए

उप राज्यपाल ने सोमवार को भी डीडीए के दो सहायक अभियंताओं को निलंबित कर दिया था। कालकाजी एक्सटेंशन में बन रहे ईडब्ल्यूएस फ्लैट के निर्माण कार्य में कमियां पाई जाने के बाद कार्रवाई की गई थी।

डीडीए ने बिना किसी नोटिस के तोड़ी कॉलोनी : विशेष रवि

नई दिल्ली, व.सं.। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने डीडीए पर गैरकानूनी तरीके से 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी में अतिक्रमण अभियान चलाने का आरोप लगाया है।

विशेष रवि ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा, लगभग 17 परिवार बेघर हो गए हैं। डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मकानों को तोड़ा। उन्होंने डीडीए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कई अन्य संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखा है। इस गैर कानूनी कार्रवाई पर 3 दिनों के भीतर जवाब की मांग करता हूं।

विशेष रवि ने कहा कि महरौली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 1के 6/4 में 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी थी। 15 जून को डीडीए ने बिना किसी सूचना के इन मकानों को तोड़ दिया। डीडीए के लोग कॉलोनी में पहुंचे और लोगों से 5 मिनट में सभी घर खाली करने को कहा। अब वह 17 परिवार इधर उधर भटक रहे हैं।

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, JUNE 23, 2022

Over 700 houses in Kathputli Colony to be ready by Sept

New Delhi: Over five years after their houses were razed at Kathputli Colony, families living in transit camps may soon be shifting to new houses as over 700 flats are likely to get ready by September-end in the area, officials said on Wednesday.

According to the Delhi Development Authority (DDA) officials, around 2,800 flats are to be built in 14-storey towers under the in-situ rehabilitation project in Kathputli Colony, and these 700 flats will be the first lot of flats to be completed by the end of September this year.

"The work is going on at a good pace. Over 700 flats in Kathputli Colony are likely to be constructed by September 30, 2022," a DDA official said.

Officials said it is Delhi's first in-situ rehabilitation project that was conceived in 2008-09 on public private partnership, but could not be implemented because of stiff resistance from the residents of Kathputli Colony.

Kathputli Colony was a slum cluster, and the residents of the locality were mainly artists, including puppeteers, acrobats, folk musicians, magicians, and dancers, among others.

The DDA had carried out three demolition exercises in Kathputli Colony to vacate the area and the final drive was conducted in November 2017.

All houses were razed in the locality for carrying out the in-situ rehabilitation project.

Residents of the area were shifted to transit camps in Anand Parbat and Narela areas.

The construction work on the ground was started in April 2018 after Union minister Hardeep Singh Puri laid the foundation stone of the project.

The deadline to give the first lot of houses was kept as March 2019, but the project was delayed due to the Covid-19 pandemic and the ban on construction activities in the national capital due to rising pollution levels. PTI

'Financial irregularities': L-G suspends three officials

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 22

DELHI LIEUTENANT Governor Vinai Kumar Saxena Wednesday suspended three officials — two sub-divisional magistrates (SDM) and a deputy secretary posted at Chief Minister Arvind Kejriwal's office — in an alleged case of "financial irregularities".

Sources said two suspended officers are SDMs and one is a deputy secretary at CMO, who was posted as an SDM when the alleged case took place.

Earlier this week, two assistant engineers were suspended by the Delhi Development Authority (DDA) after the L-G visited the construction of the flat for the EWS (economically weaker section) category of people and found that it was in poor condition and incomplete.

The L-G also cleared the decks recently to probe allegations of "irregularities" against Public Works Department (PWD) officials in the construction of seven temporary hospitals during Covid. The move had drawn a sharp reaction from the AAP, which accused him of interfering in construction of hospitals in the city.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 23 जून 2022

एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट, न पार्किंग, न टॉयलेट्स

रीडिवेलपमेंट के लिए चुना गया कीर्ति नगर बाजार, करने होंगे कई सुधार

Photos: Sunil Katara

कीर्ति नगर बाजार में फिलहाल बेतरतीबी और बदइंतजामी का आलम नजर आता है। बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं

Sudama.Yadav@timesgroup.com

- कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में करीब 2500 से अधिक दुकानें
- 47 साल पहले मार्केट में सिर्फ 300 दुकानें शिफ्ट की गई थीं
- बरसात में भर जाता है पानी, सीसीटीवी कैमरों की भी भारी कमी

■ कीर्ति नगर: दिल्ली सरकार ने जिन 5 बाजारों को रीडिवेलप करने का प्लान बनाया है, उनमें कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट भी एक है। इसे एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कहा जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर मार्केट में कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट में पार्किंग तक नहीं है। यहां सैकड़ों दुकानें हैं और हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। हालांकि न तो महिलाओं के लिए टॉयलेट्स हैं और न ही पुरुषों के लिए। बाकी सुविधाएं भी नहीं के बराबर हैं।

पार्किंग सबसे बड़ी समस्या: कीर्ति नगर टिंबर और फर्नीचर डीलर्स असोसिएशन के प्रेजिडेंट घनश्याम कुशवाहा के अनुसार फर्नीचर मार्केट में करीब 2,500 से अधिक दुकानें हैं। यहां फर्नीचर, लकड़ी, प्लाईवुड, सोफा, पर्दे, फर्निशिंग आइटम्स खरीदने न केवल दिल्ली के, बल्कि कई राज्यों से लोग आते हैं। कम से कम रोजाना 3,000 से 5,000 हजार लोग मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं। लेकिन, पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। लोग अपनी गाड़ियां कीर्ति नगर मेन रोड पर ही खड़ी कर देते हैं। इससे मायापुरी मेट्रो स्टेशन से लेकर कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन तक करीब ढाई किमी तक रोड पर हमेशा जाम लगा रहता है। मार्केट के अंदर भी पार्किंग का कोई स्पेस नहीं है। इसलिए अंदर गलियों तक में जाम लगा रहता है। दुकानदारों की मांग है कि कम से दो या तीन पार्किंग तो कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट के आसपास होनी चाहिए।

एक भी टॉयलेट नहीं: मार्केट में आने वाले हजारों लोग और दुकानदारों के लिए एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। पुराने यूरिनल बने हैं, जो काफी गंदे रहते हैं। नियमित उनकी सफाई भी नहीं होती। वर्तमान में मार्केट की जो स्थिति है, उसके हिसाब से कम से कम 8 से 10 टॉयलेट ब्लॉक होने चाहिए। अभी जो टॉयलेट की व्यवस्था है, वह दुकानदारों ने अपनी दुकानों के अंदर ही बना रखी है।

1975 में शुरू हुई फर्नीचर मार्केट

कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट को 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था। पहले यह मार्केट पहाड़गंज के पास मोतिया खान के पास थी। इमरजेंसी के दौरान यहां से 300 फर्नीचर डीलर्स को कीर्ति नगर में शिफ्ट किया गया। इन 300 दुकानदारों को डीडीए ने प्लॉट लीज पर दिए थे। इन 300 दुकानदारों से 47 साल में 2500 से 3000 दुकानें हो गई हैं।

मॉनसून में जलभराव

मॉनसून के दौरान पूरी मार्केट में जलभराव की समस्या होती है। वजह यह है कि मार्केट को जब डीडीए ने बसाया था, तभी सीवर लाइनें भी डाली गई थीं। उन सीवर लाइनों पर तब सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर का बोझ कम था। यानी तब दुकानें कम थी। लेकिन, अब दुकानों की संख्या 2,500 से अधिक है। ऐसे में पुरानी सीवर लाइनों पर बोझ इतना अधिक बढ़ गया है कि मॉनसून में जैसे ही बारिश होती है, बरसाती पानी से ब्लॉक हो जाता है। सीवर बैक मारने लगता है और जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है। सिर्फ सीवर जाम की ही समस्या से ही मार्केट के दुकानदार परेशान नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मार्केट में खास इंतजाम नहीं हैं। पूरे मार्केट में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं।

Hindustan Times

Waterlogging occurs at major road stretches across Delhi during monsoon. AMAL KS/HT ARCHIVE

1,500 new rainwater pits to curb flooding of roads, says Sisodia

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi deputy chief minister Manish Sisodia on Wednesday said more 1,500 new rainwater harvesting pits will be ready by July 15 to curb flooding of roads during monsoon as well as recharge the groundwater table.

According to private weather forecasters, monsoon may reach Delhi by June 30.

"Work is going on a war footing ahead of the rainy season to save the rainwater in Delhi. With an aim to make Delhi self-sufficient for water, 1,548 new rainwater harvesting pits will be readied by July 15. Reviewed the ongoing work on these with all the nodal agencies," Sisodia tweeted after holding a meeting with officials to review measures being taken to prevent waterlogging ahead of the rainy season.

The meeting was attended by senior officials of the Public Works Department, the Delhi Jal Board, the Delhi Development Authority, the irrigation and flood control department, the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Council and the Delhi Urban Shelter Improvement Board.

An old drainage system, lack of adequate cleaning of drains and broken roads cause massive waterlogging on road every year during monsoon.

Delhi LG VK Saxena also held a joint meeting with Delhi chief minister Arvind Kejriwal, Sisodia and a battery of top officials from all key departments such as the chief secretary, the MCD special officer and others to review monsoon preparedness. Both the LG and the CM issued a slew of directions on Wednesday to devise comprehensive long-term measures to deal with waterlogging and overflowing drains.

As for a long-term solution to tackle the problem, the LG and the CM agreed upon a comprehensive study to find ways through which excess water could be transported to natural/artificial pits, depressions and low lying areas in the city to store it.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

www.delhi.nbt.in । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 23 जून 2022
जगतपुरी । किदवई नगर । अजीत नगर । मटियामहल । रघुबरपुरा । मदनगीर । गुजरात विहार । तिगड़ी । गगन विहार

DATED

गाजीपुर के लोग बोले, पार्कों और ठेकों के पास हो पट्रोलिंग

साफ पानी और मेट्रो की कनेक्टिविटी की मांग

Photos : Surender Kumar

Shankar.Singh@timesgroup.com

■ नई दिल्लीः डीडीए ने मयूर विहार फेज-3 की अलॉटमेंट 1990 से शुरू की थी। यहां जनता, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी समेत 20 हजार से ज्यादा फ्लैट्स हैं। यूपी के नोएडा और गाजियाबाद से सटा ये इलाका कानून व्यवस्था के नजरिए से संवेदनशील है। गाजीपुर थाना एरिया में चल रहे एनबीटी सुरक्षा कवच अभियान के तहत बुधवार को मयूर विहार फेज-3 का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया। आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और पुलिस के साथ घूमकर यहां की समस्याओं से रूबरू हुए।

हर पॉकेट में गेट लगे हैं और 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट के अलावा भीतर भी सीसीटीवी कैमरे हैं। इलाके में एक हजार से ज्यादा कैमरे हैं, जिनमें दिल्ली सरकार के भी शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल आरडब्ल्यूए की महासचिव रेनू पाल ने बताया दिल्ली सरकार की तरफ से कैमरों का एक्सेस उनके पास है। छोटी-मोटी वारदात होने पर इनका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए इनका एक्सेस मिले।

NBT सुरक्षा कवच

रात में खुले एक रास्ताः आरडब्ल्यूए बी-3 पॉकेट के अध्यक्ष राकेश चौहान ने बताया कि खोड़ा कॉलोनी से फेज-3 में आने-जाने के सात रास्ते हैं। अगर पुलिस आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर रात को सिर्फ एक रास्ता खुला रखे तो गाड़ी और घरों में चोरी पर लगाम लगेगी। रात में खुलने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात रहे।

'असामाजिक तत्वों का जमावड़ा खत्म हो'

आरडब्ल्यूए सी-4 पॉकेट के महासचिव मुरलीधरन ने बताया कि एरिया में 108 पार्क हैं। शाम को यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिनमें बाहरी ज्यादा होते हैं। तीन शराब के ठेके हैं, जिनके बाहर जमघट रहता है। शाम के समय पार्कों में और ठेकों के पास चेकिंग की दरकार है। पुलिस की तरफ से एरिया में 104 सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, जो मेन चौराहों पर लगें। इनका एक्सेस एमडब्ल्यूए या आरडब्ल्यूए को भी मिले।

"फेज-3 के फ्लैट्स को अलॉट हुए 32 साल से ज्यादा हो गए हैं। पाइपलाइन में जंग लग चुकी है, जिससे सीवर का पानी मिक्स होकर सप्लाई हो रहा है। जल बोर्ड को कई बार लिखा है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। *-राजीव वर्मा, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑल आरडब्ल्यूए*

"पीडब्ल्यूडी, डीडीए और एमसीडी ने अपने नाले-नालियों से गाद नहीं निकाली है। हल्की बारिश से भी सड़कों पर पानी आ जाता है। केरला स्कूल से पॉकेट बी-6 पुलिस चौकी तक तो पूरी सड़क भर जाती है। *-रमेश मदोलिया, अध्यक्ष, बी-2 पॉकेट आरडब्ल्यूए*

"पार्क 108 हैं, लेकिन माली सिर्फ 9। दिल्ली सरकार ने पार्कों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दो लाख रुपये (अब 3.5 लाख) देने का ऐलान किया था। दो साल से चक्कर काट रहा हूं, अब तक पैसा नहीं मिला। *-जेपी तिवारी, महासचिव, सिटिजन फोरम*

"इलाके में 50 से ज्यादा डार्क स्पॉट हैं। संबंधित विभागों को कई बार लेटर लिखे, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। इससे छेड़छाड़ और झपटमारी या लूट जैसी वारदातों का खतरा बना रहता है। *-एआर कन्नन, अध्यक्ष, बी-4 पॉकेट आरडब्ल्यूए*

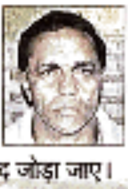

"फेज-3 के लिए मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। यहां हर वर्ग के लोग रहते हैं और मेट्रो लेने के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है। सरकार से मांग है कि इस इलाके को मेट्रो या लाइट मेट्रो से जल्द जोड़ा जाए। *-विनोद महाजन, अध्यक्ष, बी-5 पॉकेट आरडब्ल्यूए*

सिर्फ कागजों में चल रहा है अस्पताल : बीजेपी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में 7 जगहों पर अस्थायी अस्पताल बनाने के मामले में दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे बीजेपी के नेताओं ने बुधवार को किराड़ी में उस जगह का दौरा किया, जिसे अस्पताल के लिए चिह्नित किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और इस मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया गया कि जिस जगह अस्पताल बनना था, वहां एक ईंट तक नहीं लगी है। खाली जमीन पर केवल एक बोर्ड लगा है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने कागजों में इसे 458 बेड का अस्पताल बताया है, जो 28 जून 2020 से ही चल रहा है।

आदेश गुप्ता के मुताबिक, कोरोना काल में केंद्र के कहने पर डीडीए ने दिल्ली सरकार को अस्पताल बनाने के लिए किराड़ी में जमीन दी थी। दिल्ली सरकार ने यहां 458 बेड का अस्पताल बनाने की बात कही थी और कागजों में दावा किया है कि यह अस्पताल 28 जून 2020 को बनकर तैयार हो गया है। लेकिन आज वहां बंजर जमीन, कीचड़, पानी से भरे गड्ढे, झाड़ियां और एक लटकते बोर्ड के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि 2020 में बनकर तैयार हुए अस्पताल के लिए 10 अगस्त 2021 को भी टेंडर निकाला गया। इससे साफ पता चलता है कि एक ही अस्पताल के नाम पर दो बार भ्रष्टाचार किया गया।

एनडीएमसी में प्रस्ताव

एनडीएमसी काउंसिल मीटिंग बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी नेता कुलजीत सिंह चहल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया। उनकी दलील थी कि कोई भी सदस्य अगर काउंसिल मीटिंग में लगातार तीन बार बिना कारण बताए अनुपस्थित रहता है, तो नियमों के अनुसार उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS — नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार 23 जून 2022 — DATED

भ्रष्टाचार के आरोपों पर LG ने चार अफसर किए सस्पेंड

चारों अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की शिकायत मिलने के बाद उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चार अफसरों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी ऑफिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिन चार अफसरों पर सस्पेंशन की गाज गिरी है, उनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात एडहॉक दानिक्स अधिकारी प्रकाश चंद ठाकुर के अलावा वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन और विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा शामिल हैं। हौज खास के सब-रजिस्ट्रार डी सी साहू को भी सस्पेंड कर दिया है।

जैन दानिक्स अधिकारी हैं, जबकि शर्मा एडहॉक दानिक्स हैं। सीएमओ दफ्तर में तैनात पीसी ठाकुर पहले नरेला के एसडीएम थे। एसडीएम रहते एक फ्रॉड की गड़बड़ी मामले में उन्हें निलंबित किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों के खिलाफ इनके संबंधित विभाग की तरफ से ही 20 जून को एक शिकायत एलजी ऑफिस को भेजी गई थी, जिसे शुरुआती जांच में सही पाया गया और उसी के बाद इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। चारों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब इनके खिलाफ आगे की जांच करने के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, उप-राज्यपाल की संस्तुति के बाद चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की ओर से 21 जून को इन अधिकारियों को सस्पेंड करने संबंधी आदेश जारी किए गए। आदेश के प्रभावी रहने तक इन्हें सक्षम अथॉरिटी की अनुमति के बिना दिल्ली स्थित अपना मुख्यालय छोड़ने की इजाजत भी नहीं दी गई है। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई करके एलजी ने साफतौर से यह संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दफ्तरों में ईमानदारी के साथ काम हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले सोमवार को भी एलजी ने डीडीए के दो असिस्टेंट इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया था।

दिल्ली FSL में लंबित मामलों पर एलजी ने जताई नाराजगी

दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को दिल्ली फरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने 20,000 से अधिक मामलों के लंबित पड़े होने पर चिंता जताई। उन्होंने तय समय में काम पूरा करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

एलजी ने खाली पड़े विभिन्न पदों पर को जल्द से जल्द भरने का भी निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि फरेंसिक एजेंसियों से जुड़े या रिटायर्ड कर्मियों की अस्थाई तौर पर सेवाएं ली जाएं, जिससे खाली पड़े पदों से काम में आ रही दिक्कत को कंट्रोल किया जा सके। इससे इंसाफ के लिए हजारों लोगों का इंतजार खत्म होगा। एलजी ने अधिकारियों से उन मामलों की एक लिस्ट मांगी जिनकी रिपोर्ट्स टाइम फ्रेम में दी जानी थी, मगर नहीं दी जा सकी। एलजी ने पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग मॉड्यूल को विकसित करने के लिए कहा। आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय फरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के साथ गठजोड़ करने की सलाह दी।

1500 से ज्यादा नए RWH पिट्स बनेंगे

लाखों लीटर बारिश के पानी को बचाएंगे

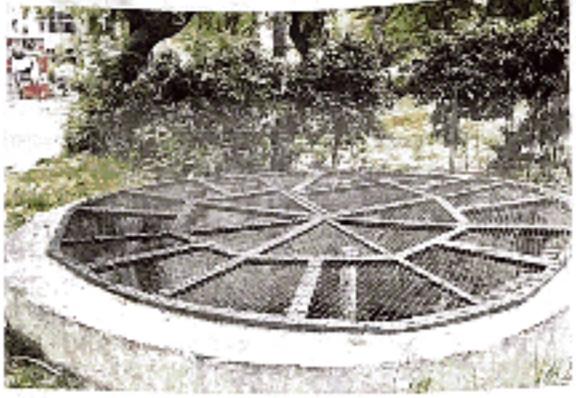

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में मॉनसून की दस्तक से ठीक पहले बारिश के पानी को सहेजने का काम तेज हो गया है। इस साल बारिश के पानी को सहेजने के लिए पूरी दिल्ली में 1500 से अधिक नए RWH (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) पिट्स बनाए जा रहे हैं। ये 15 जुलाई से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक ली।

डिप्टी सीएम ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग

इस बैठक में पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, डीयूएसआईबी आदि विभागों के अधिकारियों ने अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि बारिश का पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। राजधानी में इस पानी से भूजल बढ़ाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए पूरी दिल्ली में विभिन्न नोडल एजेंसियों के साथ मिलकर 1548 नए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाए जा रहे हैं। इन पिट्स के बाद RWH की संख्या बढ़कर 2475 हो जाएगी। उन्होंने सभी नोडल एजेंसीज को रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाने के काम को तेजी से पूरा करने की बात कही, ताकि मॉनसून के दौरान इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वैन से बारिश के पानी को संरक्षित करने के मॉडल को समझा था। इस दौरान फ्रेडी स्वैन ने बताया था कि कैसे वर्षा के जल को संरक्षित कर डेनमार्क ने खुद को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाया है।

बिना नोटिस दिए उजाड़ी SC कॉलोनी: रवि

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी विधायक का आरोप है कि डीडीए ने दिल्ली की 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय की कॉलोनी को गैरकानूनी तरीके से उजाड़ दिया। बुधवार को विधायक विशेष रवि ने कहा कि इस कार्रवाई में 17 परिवार बेघर हो गए।

डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मकानों को तोड़ा, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के पुनर्वास नियमों के अनुसार सभी परिवारों को पहले किसी और जगह घर दिए जाते हैं। इसे लेकर विशेष रवि ने डीडीए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कई अन्य संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर इस कार्रवाई को लेकर तीन दिनों के भीतर जवाब की मांग की।

आम आदमी पार्टी से करोल बाग के विधायक और दिल्ली एससी-एसटी वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन विशेष रवि ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में कहा कि महरौली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 1 के 6/4 में एससी-एसटी समुदाय की कॉलोनी के मकानों को डीडीए ने बिना किसी सूचना के तोड़ दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | JUNE 23, 2022
------------------------------DATED------------------------------

LG suspends three officials on corruption charges

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has suspended three officials including a deputy secretary in Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's office and two sub-divisional magistrates (SDMs) on corruption charges.

Sources said that Prakash Chandra Thakur posted as deputy secretary in the Chief Minister's office, Vasant Vihar SDM, Harshit Jain and Vivek Vihar SDM, Devender Sharma were suspended and disciplinary action was ordered against them.

The move reflected LG Saxena's commitment to zero tolerance to corruption, and to ensuring probity in the functioning of the government, one of the sources said.

The Lt Governor had on Monday suspended two assistant engineers of the Delhi Development Authority (DDA) after finding lapses in the construction of EWS flats in Kalkaji Extension.

Over 1,500 new rainwater harvesting pits to be ready by July 15: Sisodia

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Gearing up for the monsoon season, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Wednesday said that over 1,500 new rainwater harvesting pits will be ready by July 15 to tackle the problem of waterlogging and make the city self-reliant for water.

Sisodia said this after a review meeting with officials of all the nodal agencies for rain water harvesting pits and waterlogging. "Work is going on a war footing ahead of the rainy season to save the rainwater in Delhi. With an aim to make Delhi self sufficient for water, 1,548 new rainwater harvesting pits will be readied by July 15. Reviewed the ongoing work on these with all the nodal agencies," he said in a tweet after the meeting.

The meeting was attended by senior officials of the Public Works Department, the Delhi Jal Board, the Delhi Development Authority, the irrigation and flood control department, the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Council and the Delhi Urban Shelter Improvement Board.

Sisodia also said the number of rainwater harvesting pits will be increased to 2,475 subsequently. He said these pits will help recharge the groundwater and reduce waterlogging during monsoon.

The pits would collect storm water during monsoon, which percolates and recharges the groundwater.

Earlier this month, Chief Minister Arvind Kejriwal met Denmark's Ambassador Freddy Svane and discussed rainwater harvesting pits, avenues for collaboration in round-the-clock tap water supply, air purity and world-class roads. Kejriwal had asked Svane for a presentation on Denmark's efforts on recharging groundwater and reducing air pollution so that the Delhi government could work with the European country in implementing the model.

Dainik Bhaskar

कागजों में 2020 से चल रहे अस्पताल मौके पर अवशेष तक नहीं है : आदेश

भास्कर न्यूज़, नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने आज केजरीवाल सरकार द्वारा कोरोना काल में बनाए गए सात अस्थाई अस्पतालों में से एक किराड़ी स्थित हया हवाई अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल तो दूर वहां एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। केजरीवाल सरकार के कागजों में यह 458 बेडों का अस्पताल 28 जून 2020 से चल रहा है जबकि आज वहां ना तो अस्पताल है और ना ही उसका अवशेष। आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार के कहने पर डीडीए ने केजरीवाल सरकार को अस्पताल बनाने के नाम पर जमीन दिया था जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 458 बेडों का अस्पताल बनाने की बात कही थी। कागजों में अस्पताल 28 जून 2020 को ही तैयार कर लिया था, लेकिन आज वहां बंजर जमीन, कीचड़, जगह-जगह गड्ढों में भरा पानी और लटकते बोर्ड के अलावा कुछ नहीं है।

गुप्ता ने कहा कि यह महज संयोग नहीं है जब 2020 में बनकर तैयार हुए अस्पताल के लिए 10 अगस्त 2021 में टेंडर किया जा रहा है। मतलब एक अस्पताल बनाने के पीछे दो बार भ्रष्टाचार किया गया। पहला बिना बनाए इसको कागजों में दिखा दिया गया कि अस्पताल बनकर तैयार है और दूसरा 2020 में कागजों में बने बनाए अस्पताल का टेंडर अगस्त 2021 में पास किया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला
23/06/2022

दिल्ली का पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक, चंदन का नहीं दिख रहा 'चांस'

उपराज्यपाल लगातार चंदन लगाने पर दे रहे जोर, विशेषज्ञों ने कहा- दिल्ली का पारिस्थितिकी तंत्र इसके लिए अनुकूल नहीं

दिल्ली में चंदन लगाना मुनाफे का सौदा नहीं : मनोज मिश्र

फाइल फोटो

जरूरी माहौल

पारिस्थितिकी तंत्र

वर्षा जल को सहेजने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही सरकार : सिसोदिया

अमर उजाला ब्यूरो

उपमुख्यमंत्री ने कहा बनाए जा रहे हैं 1500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स

सड़क के रखरखाव में खामी पर भड़के उपमुख्यमंत्री

अमर उजाला ब्यूरो

अधिकारियों को निर्देश देते सिसोदिया। अमर उजाला

सिसोदिया ने आईटीओ से तिलक ब्रिज तक सड़क का किया औचक निरीक्षण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER दैनिक भास्कर DATED 23/06/2022

एमसीडी • अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर चलाया गया

आईटीओ के पास 50 से अधिक अवैध पक्के निर्माण व झुग्गियां हटाई गई

आईटीओ कब्रिस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के आस-पास दिनभर चलाया गया अभियान

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक बार फिर बुधवार को अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान आईटीओ स्थित कब्रिस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के आस-पास चलाया गया। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर और पुलिस टीम के साथ अधिकारी पहुंचे। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई में 3 जेसीबी मशीन, 5 ट्रकों एवं मार्शलिंग के द्वारा सड़क पर बनाए गए लगभग 50 पक्के निर्माण जैसे दुकान, गोदाम, ऑफिस, चाय की दुकानें इत्यादि को हटाया गया। इस कार्रवाई में लगभग 1800 वर्गमीटर सार्वजनिक भूमि को कब्जामुक्त किया गया। एमसीडी कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई कर रही है।

एमसीडी के अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को कार्रवाई शुरू करने से पहले अपने मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान किए गए थे। फिलहाल अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू है। एमसीडी का कहना है कि उसने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर अभियान के लिए पहले से पर्याप्त पुलिस तैनाती की मांग की थी। एमसीडी के कार्यकारी अभियंता (मध्य क्षेत्र) द्वारा दिल्ली पुलिस को भेजे गए पत्र में कहा गया कि नगर निगम ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में टाइम्स ऑफ इंडिया भवन के पीछे सार्वजनिक सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की योजना बनाई है। अनुरोध है कि कृपया कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला पुलिस के साथ पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराएं।

डीडीए ने महरौली में गैरकानूनी तरीके से उजाड़ी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी, 17 परिवार हुए बेघर

नई दिल्ली | आप विधायक विशेष रवि ने कहा कि भाजपा की डीडीए ने गैरकानूनी तरीके से 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी को उजाड़ दिया। लगभग 17 परिवार बेघर हो गए। डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मकानों को तोड़ा, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के पुनर्वास नियमों के अनुसार सभी परिवारों को पहले किसी अन्य जगह रहने के लिए घर दिए जाते हैं। इस मामले में नियमों का साफ उल्लंघन हुआ। मैंने डीडीए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कई अन्य संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखा है। इस गैर कानूनी कार्रवाई पर 3 दिनों के भीतर जवाब की मांग किया है। आम आदमी पार्टी से करोल बाग के विधायक विशेष रवि ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महरौली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नं 6/4 में 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी थी।

बारिश का पानी बचाने को युद्धस्तर पर काम

1500 से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनेंगे

दिल्ली में कई लाख लीटर वर्षा जल को संग्रहित करने में मिलेगी मदद: सिसोदिया

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

पानी की किल्लत की लगातार समस्या झेलती आ रही है दिल्ली सरकार ने इस मानसून में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार इस साल की बारिश में पूरी दिल्ली में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए 1500 से अधिक नए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाए जा रहे हैं जो 15 जुलाई से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे लेकर जल, पीडब्ल्यूडी व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि वर्षा जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और दिल्ली जैसे शहर के लिए इसे संरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर हैं। हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर भूजल स्तर बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके और पानी के मामले में दिल्ली आत्मनिर्भर बन सके।

बरसात के पानी को व्यर्थ होने से बचाए अधिकारी

डिप्टी सीएम सिसोदिया ने समीक्षा बैठक में कहा कि बरसात के पानी को व्यर्थ जाने से रोकें और इसे बचाए। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी को बहने देने से रोककर इन पिट्स को भरने का काम किया जाएगा जिसकी मदद से हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर पाएंगे और बरसात में व्यर्थ बहने वाले लाखों लीटर पानी को स्टोर कर पाएंगे। उन्होंने सभी नोडल एजेंसीज को रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाने के काम को तेजी से पूरा करने की बात कही ताकि मानसून के दौरान इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए दिल्ली सरकार डेनमार्क के यहां जल संरक्षण मॉडल को भी अपनाने का विचार कर रही है।

बहुत सामान्य होती है रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट्स

डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की कार्यप्रणाली बहुत सामान्य होती है जिसमें जमीन पर रोशनदार गड्ढे बनाए जाते हैं। बरसात के दौरान बारिश के पानी को इन गड्ढों के माध्यम से एकत्र किया जाता है और यह पानी जमीन के अंदर जाता है जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है। जिस तेजी से भूजल स्तर कम होता जा रहा है, उसे देखते हुए वर्तमान में जल संरक्षण के ऐसे उपाय बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME पंजाब केसरी 23 जून, 2022 ▶ गुरुवार DATED

समीक्षा बैठक | 15 जुलाई से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे 1500 से अधिक नए गड्ढे

सरकार गड्ढों में लाखों लीटर बारिश के पानी का करेगी संचयन: सिसोदिया

● हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर भूजल स्तर बढ़ाना चाहते हैं: उपमुख्यमंत्री

▸▸ उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मनीष सिसोदिया।

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली सरकार ने बारिश के पानी को एकत्र करने की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस साल की बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए दिल्ली सरकार 1500 से अधिक नए गड्ढों को बना रही है।

ये सभी गड्ढे 15 जुलाई से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। इस बात की जानकारी बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद दी। समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी), डूसिब के उच्चाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में नए बनाए जा रहे वर्षा जल संचयन गड्ढों से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। सिसोदिया ने इस मौके पर कहा कि वर्षा जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और दिल्ली जैसे शहर के लिए इसे संरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर हैं। हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर भूजल स्तर बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके और पानी के मामले में दिल्ली आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए पूरी दिल्ली में विभिन्न नोडल एजेंसीज साथ मिलकर 1548 नए वर्षा जल संचयन गड्ढे बना रही है, जिसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 2475 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बरसात के पानी को व्यर्थ बहने देने से रोककर इन गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा जिसकी मदद से हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर पाएंगे और बरसात में व्यर्थ बहने वाले लाखों लीटर पानी को स्टोर कर पाएंगे। उन्होंने सभी नोडल एजेंसीज को वर्षा जल संचयन गड्ढे बनाने के काम को तेजी से पूरा करने की बात कही ताकि मानसून के दौरान इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

डेनमार्क के मॉडल को दिल्ली सरकार अपनाएगी

दिल्ली सरकार दिल्ली को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस बाबत पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन से मुलाकात की थी और डेनमार्क के वर्षा जल संचयन मॉडल को समझा था। इस दौरान फ्रेडी स्वेन ने बताया था कि कैसे वर्षा जल को संरक्षित कर डेनमार्क ने स्वयं को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाया है।

ऐसे काम करते हैं वर्षा जल संचयन गड्ढे

वर्षा जल संचयन गड्ढों की कार्यप्रणाली बहुत सामान्य होती है जिसमें जमीन पर औसत गड्ढे बनाए जाते हैं। बारिश के पानी को इन गड्ढों के माध्यम से एकत्र किया जाता है और यह पानी जमीन के अंदर जाता है जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है। जिस तेजी से भूजल स्तर कम होता जा रहा है, उसे देखते हुए वर्तमान में जल संचयन के ऐसे उपाय बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं।

आप विधायक विशेष रवि ने लगाया आरोप

डीडीए ने गैरकानूनी तरीके से उजाड़ी लोगों की कॉलोनी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक विशेष रवि ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीडीए ने गैरकानूनी तरीके से 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी को उजाड़ दिया। लगभग 17 परिवार बेघर हो गए। रवि ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6/4 में 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी थी। जिसमें लगभग 17 परिवार रह रहे थे। 15 जून को डीडीए ने बिना किसी सूचना के इनके मकानों को तोड़ दिया। जबकि केंद्र और राज्य सरकार के पुनर्वास नियमों के अनुसार सभी परिवारों को पहले किसी अन्य जगह रहने के लिए घर दिए जाते हैं। इस मामले में नियमों का साफ उल्लंघन हुआ। रवि ने डीडीए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कई अन्य संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर इस गैर कानूनी कार्रवाई पर 3 दिनों के भीतर जवाब की मांग की है। रवि ने बताया कि 15 जून को डीडीए के लोग कॉलोनी में पहुंचे और लोगों से 5 मिनट में सभी घर खाली करने को कहा। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि हमारी तो झुग्गी भी नहीं है, यह तो पक्के मकान हैं फिर इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है। हमारे पास सभी कागज भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, वोटर कार्ड है। यह सब सुनने के बावजूद डीडीए के लोगों ने उनके मकान तोड़ दिए। विशेष रवि ने कहा कि भाजपा शासित डीडीए ने गैर कानूनी तरीके से मकानों को तोड़ा है। जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने इसका कारण पूछा। जवाब में उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी के सामने कुछ होटल और शोरूम बने हुए हैं, उनके मालिक नहीं चाहते थे कि सामने इस तरह की बस्ती हो। विशेष रवि ने कहा कि अब यह 17 परिवार इधर उधर भटक रहे हैं।

कॉलोनी में 40 सालों से रह रहे थे लोग, बिना किसी नोटिस के तोड़े मकान : विशेष रवि

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
THURSDAY, 23 JUNE, 2022 | NEW DELHI ------------------------------------ DATED ----------------------

Dy Secy in CM's office and 2 SDMs suspended by L-G Saxena

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: A deputy secretary in Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's office and two sub-divisional magistrates (SDMs) have been suspended by Lt Governor V K Saxena on corruption charges, official sources said on Wednesday.

Prakash Chandra Thakur posted as deputy secretary in the chief minister's office, Vasant Vihar SDM Harshit Jain and Vivek Vihar SDM Devender Sharma were suspended and disciplinary proceedings ordered against them, sources said.

The move reflected L-G Saxena's commitment to zero tolerance to corruption and ensuring probity in the functioning of the government, one of the sources said.

The lieutenant governor had on Monday suspended two assistant engineers of the Delhi Development Authority (DDA) after finding lapses in the construction of EWS flats in Kalkaji Extension.

5 yrs on, Kathputli Colony residents to finally shift to new houses by Sept-end

NEW DELHI: Over five years after their houses were razed at Kathputli Colony here, families living in transit camps may soon be shifting to new houses as over 700 flats are likely to get ready by September-end in the area, officials said on Wednesday.

According to Delhi Development Authority (DDA) officials, around 2,800 flats are to be built in 14-storey towers under the in-situ rehabilitation project in Kathputli Colony, and these 700 flats will be the first lot of flats to be completed by the end of September this year.

"The work is going on at a good pace. Over 700 flats in Kathputli Colony are likely to be constructed by September 30, 2022," a DDA official said.

Officials said it is Delhi's first in-situ rehabilitation project that was conceived in 2008-09 on public private partnership, but could not be implemented because of stiff resistance from the residents of Kathputli Colony.

FILE PIC

Kathputli Colony was a slum cluster and residents of the locality were mainly artists, including puppeteers, acrobats, folk musicians, magicians, dancers, among others.

The DDA had carried out three demolition exercises in Kathputli Colony to vacate the area and the final drive was conducted in November 2017. All houses were razed in the locality for carrying out the in-situ rehabilitation project.

Residents of the area were shifted to transit camps in Anand Parbat and Narela areas.

The construction work on the ground was started in April 2018 after Union minister Hardeep Singh Puri laid the foundation stone of the project. The deadline to give the first lot of houses was kept as March 2019, but the project was delayed due to COVID-19 pandemic and the ban on construction activities in the city due to rising pollution levels. AGENCIES

Amar Ujala

विधायक ने लगाया बिना नोटिस मकान तोड़ने का आरोप

नई दिल्ली। आप विधायक विशेष रवि ने आरोप लगाया है कि डीडीए ने गैरकानूनी तरीके से 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी को उजाड़ दिया। लगभग 17 परिवार बेघर हो गए। डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मकानों को तोड़ा, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के पुनर्वास नियमों के अनुसार परिवारों को पहले किसी अन्य जगह रहने के लिए घर दिए जाते हैं। इस मामले में नियमों का साफ उल्लंघन हुआ।

बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में आप विधायक विशेष रवि ने कहा कि महरौली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड एक के 6/4 में 40 साल पुरानी एससी-एसटी समुदाय के लोगों की कॉलोनी थी। इसमें लगभग 17 परिवार रह रहे थे। डीडीए ने 15 जून को बिना किसी सूचना के उनके मकानों को तोड़ दिया। इस दौरान लोगों ने अपने मकानों के कागज, आधार कार्ड, बिजली का बिल, वोटर कार्ड भी दिखाए, लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और उनके मकान तोड़ दिए। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | THURSDAY, 23 JUNE, 2022 ----------DATED----------

'WORK IS PROGRESSING ON A WAR FOOTING AHEAD OF THE RAINY SEASON'

1,548 new rainwater harvesting pits will be ready by July 15: Deputy CM

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Wednesday said over 1,500 new rainwater harvesting pits will be ready by July 15 to tackle the problem of waterlogging and make the city self-reliant for water.

Sisodia said this after a review meeting with officials of all the nodal agencies for rainwater harvesting pits and waterlogging ahead of the monsoon season.

"Work is going on a war footing ahead of the rainy season to save the rainwater in Delhi. With an aim to make Delhi self-sufficient for water, 1,548 new rainwater harvesting pits will be readied by July 15. Reviewed the ongoing work on these with all the nodal agencies," he said in a tweet after the meeting.

The meeting was attended by senior officials of the Public Works Department, the Delhi Jal Board, the Delhi Development Authority, the irrigation and flood control department, the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Council and the Delhi Urban Shelter Improvement Board.

Sisodia also said the number of rainwater harvesting pits will be increased to 2,475 subsequently. He said these pits will help recharge the groundwater and reduce waterlogging during monsoon.

The pits would collect storm water during monsoon, which percolates and recharges the groundwater.

Earlier this month, Chief Minister Arvind Kejriwal met Denmark's Ambassador Freddy Swain and discussed rainwater harvesting pits, avenues for collaboration in round-the-clock tap water supply, air purity and world-class roads.

Kejriwal had asked Swain for a presentation on Denmark's efforts on recharging groundwater and reducing air pollution so that the Delhi government could work with the European country in implementing the model here.

Highlights

- Sisodia also said the number of rainwater harvesting pits will be increased to 2,475 subsequently
- He said these pits will help recharge the groundwater and reduce waterlogging during monsoon

23 जून • 2022
राष्ट्रीय सहारा

कागजों पर चल रहा किराड़ी का अस्पताल : भाजपा

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली भाजपा ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार की ओर से किराड़ी में बनवाया गया अस्पताल सिर्फ कागजों में चल रहा है। बुधवार को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता व सांसद मनोज तिवारी ने मौके का दौरा किया। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार के कहने पर डीडीए ने केजरीवाल सरकार को अस्पताल बनाने के नाम पर जमीन दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 458 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की बात कही थी और कागजों में अस्पताल 28 जून 2020 को ही तैयार कर लिया था, लेकिन वहां बंजर जमीन, कीचड़, जगह-जगह गड्ढों में भरा पानी और लटकते बोर्ड के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग नहीं है कि 2020 में बनकर तैयार हुए अस्पताल के लिए 10 अगस्त 2021 में टेंडर किया जा रहा है। मतलब एक अस्पताल बनाने के पीछे दो तरह भ्रष्टाचार किया गया। पहला बिना बनाए इसको कागजों में दिखा दिया गया कि अस्पताल बनकर तैयार है और दूसरा 2020 में कागजों में बने बनाए अस्पताल का टेंडर अगस्त 2021 में पास किया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि अस्पताल के नाम पर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि अस्पताल के नाम पर करप्शन किया गया है। जनता को उपचार देने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने इसी अस्पताल में 600 मरीजों का इलाज कराने की बात कही थी, लेकिन यह इलाज कहां हुआ, समझ से परे है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU
THURSDAY, JUNE 23, 2022

Deputy Secy. in CMO, 2 SDMs suspended by L-G

Action on charges of 'corruption, non-probity' in functioning

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

A deputy secretary currently attached to Chief Minister Arvind Kejriwal's office and two Sub-Divisional Magistrates (SDMs) were suspended by Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena on Wednesday on charges of "corruption and non-probity" in their functioning.

Disciplinary proceedings have been initiated against Prakash Chandra Thakur, posted as a Deputy Secretary in CMO, Vasant Vihar SDM Harshit Jain and Vivek Vihar SDM Devender Sharma, said sources said.

L-G Vinai Kumar Saxena

Previous complaints

According to the sources, the directions were issued on the basis of complaints alleging financial and procedural lapses by the officials on which action was pending. The complaint against Mr. Thakur, a source added, pertained to his previous posting in the Revenue Department and was not related to his present position in the CMO.

'Postings L-G's domain'

A Delhi government source said transfers and postings of officials fell under the L-G's domain and the former did not have a say in them – whether these pertained to the Revenue Department or the CMO – at all.

Sources said the officials were placed under suspension before the completion of inquiries into the allegations against them in line with Mr. Saxena's "commitment to zero tolerance for corruption and ensuring probity in the functioning of the government".

Reacting to the development, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said "suspension on corruption charges of a deputy secretary in the CMO had exposed the hollowness of claims of honest administration" made by Chief Minister Arvind Kejriwal.

"CM claims zero tolerance on corruption but today a black sheep has been found in his own office, clearly indicating there is no monitoring against corruption in the CM office and the Delhi Secretariat," Mr. Kapoor said.

The L-G had, on Monday, suspended two assistant engineers of the Delhi Development Authority after finding lapses in the construction of flats meant for the rehabilitation of EWS citizens in Kalkaji Extension.

No hospital at site claimed by govt.: BJP

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

"Not even a brick was laid" at the site of a temporary hospital the Delhi government had announced to have set up during the second wave of COVID-19 in north Delhi's Kirari, the BJP said following a visit to the location on Wednesday.

A delegation, led by Delhi BJP president Adesh Gupta and North East Delhi MP Manoj Tiwari, said it came across only "a barren plot" and a board at the location. "During the COVID period, the DDA, on being asked by the Centre, gave this plot to the Kejriwal government for a hospital. The State government talked about setting up a 458-bed hospital, which, in its files, was ready on June 28, 2020," Mr. Gupta said.

When reached for a comment, AAP spokesperson did not respond.

L-G V.K. Saxena recently granted permission to the Anti-Corruption Branch to probe allegations of corruption in award of contract for setting up seven temporary hospitals.